भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये ऐतिहासिक फैसले

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

रोमेश *????? ????? ???????? ?????? (1950)* मामले ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत **स्वतंत्र भाषण की रक्षा करने,** राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने और भारत में **प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को आकार देने के लिये एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की।**

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 मामले के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 1950 में मद्रास सरकार ने पुलिस हिंसा की रिपोर्टिंग करने के कारण साप्ताहिक पत्रिका*????????????? ??* **मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम** के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण 22 कम्युनिस्ट मारे गए, इस प्रतिबंध को बाद में**उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।**
- **उच्चतम न्यायालय का फैसला:**
  - मई 1950 में उच्चतम न्यायालय ने **मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया,** जिसमें कहा गया कि **स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये और इसे "राज्य की सुरक्षा" से जोड़ा जाना चाहिये।**
    - न्यायालय ने राज्य की मनमाना रूप से सेंसर करने की शक्ति को सीमित करते हुए स्पष्ट किया कि **"लोक व्यवस्था" को "राज्य सुरक्षा" के बराबर नहीं माना जा सकता।**

नोट:

- *?????? ????? ????? ???????? ??????, 1950* मामले के प्रत्युत्तर में, सरकार ने वर्ष **1951 में पहला सांविधानिक संशोधन अधिनियम** पेश किया, जिसमें मुक्त भाषण पर **अनुच्छेद 19(1)(a) में "युक्तियुक्त प्रतिबंध" जोड़े गए, जिसमें लोक व्यवस्था, अपराध-उद्दीपन** और विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे आधार शामिल थे।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण मामले कौन-से हैं?

- ***??? ????? ????? ???????? ??????, 1950:*** *???? ????? ??????* में, सर्वोच्च न्यायालय ने *???????????* पत्रिका पर लगाए गए **समाचार पत्र की पूर्व सेंसरशिप की आवश्यकता वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया** और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सेंसरशिप वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
  - सर्वोच्च न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि **मूल अधिकार पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिये जब लोक व्यवस्था को स्पष्ट खतरा** हो या **हिंसा को उकसाया जा रहा हो।**
  - इस निर्णय ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि प्रकाशन पर कोई भी पूर्व रोक असंवैधानिक है।
- ***????? ??????? ???????? ????? ????? ????, 1961*: सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 को रद्द कर दिया,** जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के मूल्य निर्धारण, विज्ञापन स्थान और सप्लीमेंट संबंधी **प्रतिबंध लगाए गए थे।**
  - न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि ये प्रतिबंध **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन हैं,** क्योंकि इनका **अनुचित रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है।**
- ***?????? ??????? ???? ?????? ????? ????? ????, 1973: ?????? ????????? ????????? ?? ?? ???????????? ????????? ????? ?? ?????? ?? ?????, ?????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ????????? ????? ????? ????? ??????? ?? ?????? ??***

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **इस तरह के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित** होने के साथ **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन** हैं।

- ***[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 1985: [illegible]*** *1981* ***[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]***
  - इसे समाचार पत्रों के संचालन को आर्थिक रूप से कठिन बनाकर **प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के** एक अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखा गया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **प्रेस की स्वतंत्रता,** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य पहलू है तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों पर **अत्यधिक कराधान को अनुचित ठहराया** तथा इस बात पर बल दिया कि कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित होना चाहिये।

- ***[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 2015: [illegible] [illegible]*** **मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने **IT अधिनियम की धारा 66A** को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि यह **अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक थी,** जिससे **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत **स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन** हुआ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

[illegible]:

प्रश्न. नौवीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था? (2019)

(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) लाल बहादुर शास्त्री
(c) इंदिरा गांधी
(d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/landmark-rulings-safeguarding-freedom-of-press-in-india